और ... एक शेर

सारी दुनिया के हैं वो मेरे सिवा
मैंने दुनिया छोड़ दी जिनके लिए

-अमीर मीनाई

लोकमत समाचार

तमसो मा ज्योतिर्गमय

अपने अंदर से अहंकार को निकालकर खुद को हल्का कर लो, ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है.
■ टॉलस्टॉय

संपादकीय

'सूखे की राजधानी' न बनने पाए महाराष्ट्र

गत दिनों राज्य के सूखाग्रस्त इलाकों में हुई बारिश ने राहत बरसाई है. जाते हुए मानसून ने मराठवाड़ा और विदर्भ के बांधों में जलस्तर बढ़ा दिया है. इससे जहां एक ओर जलापूर्ति के लिए टैंकरों की फेरियां कम हुई हैं, वहीं अनेक स्थानों पर पशु चारा छावनियां भी बंद हो गई हैं. वापसी की बारिश के कारण 70 लाख हेक्टेयर में रबी की फसल होने की संभावना जाग गई है. राज्य में जलसंग्रहण के लिए चल रही जलयुक्त शिवार योजना को भी इससे फायदा हुआ है. तात्कालिक संतोष की बात यह है कि बांधों का जलस्तर बढ़ने से बहुत से जिलों में जून तक तथा अवर्षा झेल रहे इलाकों में मार्च तक पानी की समस्या नहीं होगी. इस बारिश से राज्य सरकार ने भी राहत की सांस ली है. हालांकि, सूखे का संकट अब भी बरकरार है. साल दर साल मानसून की अनियमितता किसानों के लिए लगातार परेशानी का कारण बनी हुई है. अन्नदाता के पास ही खाने को कुछ नहीं है. आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है. महाराष्ट्र समेत पूरे देश में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है. कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ की आपदा बनी रहती है और इस अवर्षा का नतीजा है कि इस साल भी मराठवाड़ा का सोना खराब हो चुका है. सोना, यानी मौसंबी जो मराठवाड़ा में किसानों की आमदनी का मुख्य जरिया है, लेकिन बीते तीन-चार साल से लगातार पड़ रहे सूखे ने इसे खत्म कर दिया है. पिछले पांच सालों में मानो यह पैटर्न बन गया है कि जून माह में कुछ बारिश होती है, किसान जब तक बुआई पूरी करता है, बारिश बंद हो जाती है. बारिश जब दोबारा अगस्त आखिर या सितंबर माह में लौटती है तब तक फसल चौपट हो चुकी होती है. किसान न तो पुराना कर्ज चुकाने की स्थिति में रहता है, न नया लेने की. पिछले चार सालों में राज्य की हालत यह हो गई है कि देश के किसी भी राज्य से अधिक अकालग्रस्त क्षेत्र महाराष्ट्र में हैं. इसकी वजह मानसून की मनमानी तो है ही, पर यह मानवनिर्मित संकट भी है. वृक्षों की अधाधुंध कटाई, अधूरी पड़ी जल परियोजनाएं और जलसंसाधनों का जरूरत से अधिक दोहन का दुष्परिणाम सूखा-अकाल के रूप में सामने आ रहा है. दीर्घकालिक कृषि और फसल पद्धति में परिवर्तन समय की मांग है. वैज्ञानिक बारिश के पैटर्न को लेकर भी चिंतित हैं. बरसात के मौसम में भले ही पानी का कोटा पूरा हो जाता हो लेकिन जब खेतों को इसकी ज्यादा जरूरत होती है, तब उन्हें यह नहीं मिल पाता. थोड़े समय में बहुत अधिक बारिश खेती के लिए नुकसानदायक ही साबित होती है. राज्य के 90 लाख लघु और सीमांत किसान इस समय मौसम की मार से पीड़ित हैं. राज्य की सबसे बड़ी जरूरत है जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना बनाना और उस पर ईमानदारी से अमल करना. अधूरी पड़ी परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करना और उपलब्ध जलसंसाधनों का समुचित दोहन करना. अब भी यदि इस पर गंभीरता से विचार कर दीर्घकालिक उपाय न किए गए तो राज्य को देश की 'अकाल राजधानी' बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. ■■

टाइम पास

''देखिए, बड़े बाबू, मुझे अपने ऑफिस में साफ-सुथरा कामकाज पसंद है. किसी प्रकार की अनुशासनहीनता को मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता. आप फौरन उस आदमी को बुलाइए, जो बाहर घूमकर टाइम पास कर रहा है. मेरे सामने उसके हाथ में पांच हजार रुपए पकड़ा कर उसकी छुट्टी करो. आज के बाद वो नौकरी पर नहीं दिखना चाहिए.'' कहकर सेठजी अपनी कुर्सी पर डट गए.

लघुकथा

ओमप्रकाश सोनी

इसके पहले जब चमचमाती कार फैक्टरी के भीतर घुसी तो उसमें से उतरते वक्त सेठजी की नजर उस आदमी पर पड़ गई थी, जो सिगरेट के छल्ले छोड़ते हुए इधर-उधर टहल रहा था. फिर क्या था. ऑफिस में प्रवेश करते ही सेठजी ने बड़े बाबू को तुरंत हाजिर होने का फरमान जारी कर दिया था. चौकीदार को भेजकर उस सिगरेट फूंकने वाले व्यक्ति को केबिन में बुलाया गया. स्वयं सेठजी ने उसके हाथ में पांच हजार रुपए पकड़ा कर उसे बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया.

करीब एक घंटे बाद चाय की चुस्कियों के साथ सेठजी का गुस्सा शांत हुआ तो बड़े बाबू को बुलाकर पूछ ही लिया ''यह तो बताइए, हमने जिस लापरवाह आदमी को नौकरी से निकाला, वो हमारे यहां किस डिपार्टमेंट में काम करता था.''

बड़े बाबू ने माथे के पसीने को पोंछते हुए कहा ''हुजूर, आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया. वह अपने यहां का कर्मचारी नहीं था. वह तो कूरियर कंपनी से पार्सल लेकर आया था.'' ■■

चुनावी दौड़ में बजती ढपली

आलोक मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तर-भारत में चुनावी दौड़ के दौरान आरक्षण का मुद्दा लगभग तीन वर्षों से उठता रहा है. इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा आरक्षण नीति पर पुनर्विचार के लिए समिति के गठन की सलाह तथा भाजपा की तत्काल सफाई पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए. महाभारत काल से 'युद्ध' में सुविधानुसार 'धर्म-अधर्म', 'नैतिक-अनैतिक' की व्याख्या करते हुए केवल विजय पर ध्यान केंद्रित किया जाता रहा है. राजनीतिक युद्ध में भी 'नरम-गरम', 'नेहरू फोरम - सोशलिस्ट फोरम', 'स्वदेशी जागरण मंच' - 'अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद' जैसे मंचों के जरिए परस्पर विरोधी विचार एक ही पार्टी के खेमों द्वारा व्यक्त किए जाते रहे हैं. इसे कहते हैं - चित भी मेरी, पट भी मेरी. भागवत जी की टिप्पणी कुछ बड़बोले नेताओं की तरह बिना सोचे-समझे सामने नहीं आई है. बिहार विधानसभा में संघ के विचारों से जुड़े एक वर्ग तथा भाजपा के ऊंची जाति के मतदाताओं में नई उम्मीद जगाने में भागवत का 'आरक्षण काट' हथियार उपयोगी हो सकता है. वहीं भाजपा में नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने अपने को 'पिछड़ों का सिरमौर' घोषित करते हुए पिछड़ों-अति पिछड़ों को अपनी ओर खींचने का ढोल बजा रखा है. भागवत की टिप्पणी पर नीतीश-लालू और कांग्रेस गठबंधन की तीखी प्रतिक्रिया भी पिछड़ों के 'फिक्स डिपाजिट वोट' को सुरक्षित रखने की कोशिश है. वैसे कांग्रेस का एक खेमा भी 'अगड़ों' को अपनी ओर पुनः जोड़ने की फिराक में है.

चाहे-अनचाहे 'आरक्षण नीति' की समीक्षा पर बहस तो शुरू हो ही गई है. संघ-भाजपा नेतृत्व के लिए यह पहला अवसर नहीं है. संघ के पूर्व सरसंघचालक प्रो. राजेंद्र सिंह ने 4 अक्तूबर 1997 को दिल्ली में ऑन रिकार्ड इंटरव्यू में मुझसे कहा था - ''देश की राजनीति में आरक्षण के नाम पर जातिवाद का विष विश्वनाथ प्रताप सिंह ने घोला था. अपने स्वार्थ के लिए - देवीलाल और चौटाला को हटाने के लिए. यह विष अभी कुछ समय तकलीफ देगा, लेकिन इसका भी अंत समीप आ गया है.'' इस टिप्पणी के समय उत्तर प्रदेश में पिछड़े वोट बैंक के लिए कल्याण सिंह को पुनः मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भाजपा में भी कलह मची हुई थी. मतलब संघ और भाजपा दुधारी तलवार का इस्तेमाल कर रहे थे.

> संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा आरक्षण नीति पर पुनर्विचार के लिए समिति के गठन की सलाह तथा भाजपा की तत्काल सफाई पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए.

पिछड़ों को आरक्षण का मुद्दा इंदिरा-राजीव गांधी के सत्ताकाल में सर्वाधिक उछला था. विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तो 1989 में इसे हथियार बनाया. लेकिन राजीव गांधी सत्ता में आने के तत्काल बाद 1985 में विधानसभा चुनावों के दौरान 'आरक्षण' के मुद्दे पर खुलकर बोल रहे थे. राजीव गांधी ने 2 मार्च 1985 को एक औपचारिक इंटरव्यू में मुझसे ही कहा था - ''संविधान बनाते समय की गई आरक्षण की व्यवस्था का पिछले वर्षों के दौरान बहुत राजनीतिकरण हो गया है.'' राजीव की यह टिप्पणी छपने पर संघ-भाजपा के कुछ बड़े नेता प्रसन्न हुए थे. पुराने दिग्गज नेता और उनके करीबी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि इंदिरा-संजय-राजीव गांधी के कुछ कदमों का संघ नेता समर्थन करते थे. इंदिरा युग के गुप्तचर प्रमुख टी.राजेश्वर की नई पुस्तक में भी यह तथ्य उजागर हुआ है कि संघ के कुछ बड़े नेता इमरजेंसी के कुछ कदमों के समर्थक थे. इसी तरह पंजाब में आतंकवाद समर्थक गुटों के विरुद्ध अभियान, वीपी सिंह की आरक्षण नीति के विरुद्ध आंदोलन में संघ-कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए थे. आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर के ताले राजीव गांधी की सरकार ने खुलवाए थे. तब नारायणदत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे. इसलिए राजनीति में 'समय और सुविधा' के साथ विचारों और व्यक्तियों का समर्थन अथवा विरोध होता रहा है. दुर्भाग्य यह है कि जाति, धर्म, भाषा पर भेदभाव नहीं करने की संवैधानिक शपथ के बावजूद राजनेता चुनाव के वक्त ऐसे मुद्दों पर समाज के विभिन्न वर्गों को बांटने-लड़ाने की कोशिश करते हैं. बिहार, उत्तर-प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में पिछले कुछ चुनावों में विभिन्न पार्टियां खुलकर जातिकार्ड खेलती हैं. सवाल यह है कि सत्ता में आने के बाद केंद्र या राज्यों में उनकी सरकारें रोजगार के अवसर उपलब्ध करा पा रही हैं? सरकारी रिकार्ड से साबित हो सकता है कि विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संस्थानों में नई नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है. हजारों स्थान रिक्त पड़े हुए हैं और कुछ सेवानिवृत्त अथवा नए लोगों को कांट्रैक्ट पर जरूरी काम के लिए रखा जा रहा है. 'डिजिटल इंडिया' के दौर में न्यूनतम कर्मचारियों को रखकर बड़ी कंपनियों को सफलता मिल रही है. उत्तर प्रदेश-बिहार या मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों के लिए बनी औद्योगिक बस्तियों की सैकड़ों इकाइयों पर ताले पड़ चुके हैं. जरूरत है- सबको शिक्षा की सर्वोत्तम सुविधा दिए जाने की. अच्छी शिक्षा, स्वरोजगार के अवसर तथा स्वास्थ्य एवं आवास की न्यूनतम सुविधाएं मिलने से संपूर्ण समाज और राष्ट्र की प्रगति हो सकती है. ■■

बुनियादी ढांचे से ही विकास संभव

डॉ. जयंतीलाल भंडारी
प्रख्यात अर्थशास्त्री

यकीनन इन दिनों भारत के विकास की नई संभावनाएं बताने वाली जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं, उनमें एक मत से कहा गया है कि भारत द्वारा आर्थिक मौकों को मुट्ठी में लेने और विकास दर बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास पहली जरूरत है. हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज द्वारा प्रकाशित नवीनतम अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की विकास दर 2015-16 में सात फीसदी रहेगी. लेकिन रिपोर्ट में यह खास बात भी कही गई है कि यदि भारत अटके पड़े आर्थिक सुधारों व अटकी पड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति दे तो विकास दर 10 फीसदी तक पहुंच सकती है. उद्योग मंडल एसोचैम के द्वारा पिछले दिनों प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट में भी कहा गया है कि देश के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है. रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में अटकी पड़ी परियोजनाओं में सबसे अधिक बुनियादी ढांचा क्षेत्र की हैं. उल्लेखनीय है कि सितंबर 2015 के पहले सप्ताह में तुर्की में जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत बुनियादी ढांचे पर जोर देकर जहां ग्रोथ की संभावना की अनुकूलता रख सकता है वहीं वैश्विक आर्थिक निराशाओं के बीच वह वैश्विक आर्थिक अवसरों का लाभ ले सकता है.

इसी तरह जर्मनी स्थित वैश्विक सलाहकार व शोध कंपनी डेल्फी ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि भारत में बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दिए जाने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने और आर्थिक विकास के मौकों को मुट्ठी में करने की दृष्टि से भारत अनुकूल स्थिति में होगा. कहा गया है कि भारत ब्रिक्स के देशों यानी ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका से भी बेहतर स्थिति में है. अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तेजी और चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी की हालत में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास की नई प्रवृत्ति दिखाई दे रही है. विश्व अर्थव्यवस्था में कई देश जहां निम्न विकास दर से जूझ रहे हैं, वहीं भारत की वृद्धि दर चीन से आगे निकल सकती है. यदि भारत बुनियादी ढांचे की बाधाओं को दूर करे तो 2019 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 2009 की तुलना में दोगुनी हो सकती है. 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ हालिया वैश्विक घटनाक्रम और भारत के लिए अवसर विषय पर चर्चा की. चर्चा के दौरान वैश्विक सुस्ती से निपटने और भारत के लिए मौके तलाशने के मद्देनजर बुनियादी ढांचे के विकास और अधूरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गतिशील करने के लिए कई सुझाव आए.

देश में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं कितनी निराशाजनक स्थिति में हैं इसका

> यदि भारत बुनियादी ढांचे की बाधाओं को दूर करे तो 2019 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 2009 की तुलना में दोगुनी हो सकती है.

अंदाज 30 अगस्त को भारत सरकार के केंद्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर एवं परियोजना निगरानी विभाग के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से लगता है. उसके अनुसार मई 2015 तक केंद्रीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र से संबंधित कुल 766 केंद्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से 237 का काम समय से पीछे चल रहा था, जिनकी कुल लागत 4826 अरब रुपए है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस साल मध्य अगस्त तक केंद्र सरकार के परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) के पास 10 अरब रुपए अथवा इससे ज्यादा मूल्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण तथा ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से संबंधित 675 परियोजना प्रस्ताव आए हैं, जिनकी कुल अनुमानित लागत 28800 अरब रुपए है. पीएमजी ने इसमें से 9900 अरब रुपए की 291 परियोजनाओं को मंजूरी दी है.

हम आशा करें कि मोदी सरकार भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ढांचागत विकास के नीति-नियमों और दिशा-निर्देशों में बड़े बदलाव और उनके कारगर क्रियान्वयन की डगर पर अवश्य आगे बढ़ेगी. ■■

दूसरी यात्रा के ज्यादा सफल होने की उम्मीद

अवधेश कुमार
जाने-माने पत्रकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह दूसरी अमेरिका यात्रा होगी. संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनका दूसरा भाषण होगा. पहली अमेरिका यात्रा में उन्होंने अपनी तथा सहयोगियों की भूमिका से कामयाबी का झंडा गाड़ा था. संयुक्त राष्ट्र में उनका भाषण अन्य सभी नेताओं से अलग ऐसे मौलिक सुझावों तथा प्रस्तावों वाला था जिसके पीछे विश्व व्यवस्था का दर्शन, तार्किकता एवं व्यावहारिकता - सबका मिलन था. विश्व नेता उनके भाषण से काफी प्रभावित हुए. नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि वहीं से बदलनी आरंभ हुई. उसी का परिणाम था कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने योग के उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया एवं योग दिवस आरंभ हो चुका है. ओबामा भी उनके भाषण और नए विचारों से प्रभावित थे. मेडिसन स्क्वायर का उनका भाषण ऐसा मोड़ बिंदु साबित हुआ जिसने न केवल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मोदी के बारे में सोच को बदला, बल्कि विश्व के अनेक नेताओं को प्रभावित किया. प्रश्न है कि क्या वर्तमान दौरा उसी तरह की कामयाबी वाला होगा?

> 2014 की तुलना में मोदी की इस बार की अमेरिका यात्रा ज्यादा सघन कार्यक्रमों वाली, विस्तृत व परिणामकारी होने की उम्मीद की जा सकती है.

इस एक वर्ष में अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जर्मन चांसलर, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री, संयुक्त अरब अमीरात, पूर्वी एशिया आदि के नेताओं के साथ राजनयिक के अलावा व्यक्तिगत संबंध भी कायम हो चुके हैं जो पिछली बार नहीं थे. ओबामा के साथ उनका सीधे हॉटलाइन भी आरंभ हो गया है. अपने 26 देशों के दौरों में मोदी ने कारोबारियों, उद्योगपतियों, बैंकरों से लगातार मुलाकात करके उन्हें भारत में पूंजी लगाने को प्रेरित किया है. तो इस बार वे व्यक्तिगत संबंधों एवं छवि के मजबूत आधार पर खड़े होंगे.

पिछले वर्ष मेक इन इंडिया की घोषणा के एक महीने के अंदर ही वे अमेरिका गए थे. एक वर्ष में इस दिशा में भूमि अधिग्रहण पर पीछे हटने को छोड़कर काफी कदम उठाए गए हैं. इसलिए निवेशकों, कारोबारियों से मुलाकात में वे नए आत्मविश्वास के साथ बातें रखेंगे. पिछली बार अमेरिका की द्विपक्षीय यात्रा आरंभ होने के पूर्व अधिकतर कार्यक्रम, मुलाकातें न्यूयॉर्क में ही हुए थे. इस बार काफी विस्तृत यात्रा है. वे कई जगह जाएंगे.

इस तरह 2014 की तुलना में मोदी की इस बार की अमेरिका यात्रा ज्यादा सघन कार्यक्रमों वाली, विस्तृत व परिणामकारी होने की उम्मीद की जा सकती है. ■■

नजर के पार

शिक्षित बेरोजगारी की भयावह तस्वीर

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बना देने वालों की नींद अब टूटनी चाहिए. जिस युवा जनसंख्या के बूते इक्कीसवीं शताब्दी के भारतीय युवाओं की शताब्दी होने का दंभ भरा जा रहा है, उसे उत्तर प्रदेश में खड़ी शिक्षित बेरोजगारों की फौज ने आईना दिखा दिया है, जहां विधानसभा सचिवालय में भृत्य के महज 368 पदों के लिए 23 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं. मतलब एक पद के लिए 6000 अर्जियां! बेरोजगारी का यह सच शिक्षा के क्षरण की ऐसी बदरंग तस्वीर है, जो बड़े खतरे का संकेत दे रही है. इस सच्चाई को यदि नजरअंदाज किया गया तो अराजकता के हालात बनने में देर नहीं लगेगी. अलबत्ता समय रहते 'मेक इन इंडिया' की दिशा को लघु व कुटीर उद्योगों और 'स्किल इंडिया' को ज्ञान परंपरा की ओर मोड़ने की जरूरत है.

किसी भी विकासशील देश के लिए यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसकी युवा पीढ़ी उच्च शिक्षित होने के बावजूद आत्मनिर्भरता के लिए चपरासी जैसी सबसे छोटी नौकरी के लिए लालायित है. 21 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में चपरासी के लिए जो 23 लाख अर्जियां आई हैं,उनमें चाही गई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पांचवीं पास तो केवल 53,426 उम्मीदवार हैं, किंतु छठवीं से बारहवीं पास उम्मीदवारों की संख्या 20 लाख के ऊपर है. इनमें 7.5 लाख इंटर पास हैं. इनके अलावा 1.52 लाख उच्च शिक्षित हैं. इनमें विज्ञान, वाणिज्य और कला से उत्तीर्ण स्नातक और स्नातकोत्तर तो हैं ही, इंजीनियर और एमबीए भी हैं. साथ ही 255 अभ्यर्थी पीएचडी हैं. शिक्षा की यह सर्वोच्च उपाधि इस बात का प्रतीक मानी जाती है कि जिस विषय में छात्र ने

पीएचडी प्राप्त की है,उस विषय का वह विशेषज्ञ है. यह उपाधि महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में भर्ती किए जाने वाले सहायक प्राध्यापकों की वांछित योग्यता में जरूरी है. जाहिर है, सरकार के समक्ष यह संकट खड़ा हो गया है कि वह आवेदनों की छंटनी का आधार क्या बनाए और परीक्षा की ऐसी कौन सी तरकीब अपनाए कि प्रक्रिया पूरी हो जाए? क्योंकि जिस बड़ी संख्या में अर्जियां आई हैं, उनके साक्षात्कार के लिए 10 सदस्यीय समितियां भी बना दी जाएं तो परीक्षा निपटाने में चार साल से ज्यादा का समय बीत जाएगा. सरकारी नौकरियों में आर्थिक सुरक्षा की वजह से लगातार युवाओं का आकर्षण बढ़ रहा है.

बेरोजगारों की इस फौज ने दो बातें एक साथ सुनिश्चित की हैं. एक तो हमारे शिक्षण संस्थान समर्थ युवा पैदा करने के बजाय ऐसे बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रहे हैं, जो योग्यता के अनुरूप नौकरी की लालसा पूरी नहीं होने की स्थिति में कोई भी नौकरी करने को तत्पर हैं. दूसरे, सरकारी स्तर की छोटी नौकरियां तत्काल भले ही पद व वेतनमान की दृष्टि से महत्वपूर्ण न हों, लेकिन उनके दीर्घकालिक लाभ हैं. उत्तरोत्तर वेतनमान व सुविधाओं में इजाफा होने के साथ आजीवन आर्थिक सुरक्षा है. स्वायत्त निकायों में तो चपरासियों को भी अधिकारी बनने के अवसर सुलभ हैं.

अकसर कहा जाता है कि शिक्षा व्यक्तित्व के विकास के साथ रोजगार का मार्ग खोलती है. लेकिन चपरासी की नौकरी के परिप्रेक्ष्य में डिग्रीधारी बेरोजगारी की जो तस्वीर पेश हुई है, उसने समस्त शिक्षा प्रणाली को कठघरे में ला खड़ा किया है. ■■

तोल बोल

कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि गंवाई हुई कुर्सी कैसे वापस पाई जाए. इसलिए मथुरा में जो शिविर हुआ, वह चिंतन नहीं चिंता शिविर था.

■ नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

भारत खूबसूरत जगहों के मामले में अमीर है. हमारे देश में बेहद खूबसूरत और अनोखी जगहें हैं. इसलिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत नहीं है.

■ दीया मिर्जा, फिल्म अभिनेत्री

gñWmHñ gnXHñ :
ñd. Odñabmb XSñ
M`a Z, E[SQñ{a`b ~ñS :
{dO~ XSñ
E{SQa-BZ-Mr\ñ :
arOB XSñ
gnXH :
{dHñrg {_ I ★
★ nr. Aza. ~r. HbZZ Hñ
AZgna gnU gnXHñ` Xñ{`Ed Hñ {bE {Oá_Xza.

© लोकमत समाचार _ àHñ{eV g^r gr_Jr Hñ gdñ{YHñna bmHñ_V r{S`ñ àn`dO {b. Hñ mg ga[jV h.
bmHñ_V _r{S`ñ àn`dO {b. Hñ {bE _ÐHñ Ed àHñeHñ बालाजी मुले Ûnar bmHñ_V ¯r{S`ñ àr. {b., ñbrQ Hñ. 192, 207, 208 E _. AtB. Sr. gr. B\S{ñfQ` b E[a`ñ, ~Qr~rar, ZrJna _{ÐV Ed bmHñ_V ^dZ n. Odñhabmb Zñèñ _ñJ, ZrJna _ àHñ{eV.
P.O.BOX NO. 230 R.N.I. No. 47101/89
XaUdZ : 0712-2423527 (7 bmB'g) \ñSg : 6618555
Email : gnXHñ` : lsedit.ngp@lokmat.com
{dkmZ : advt.ngp@lokmat.com {dVaU : circ.ngp@lokmat.com

इतिहास पर नजर 23 सितंबर

आज ही के दिन 1983 में पाकिस्तान के कराची से अबू धाबी जा रहे गल्फ एयर के एक यात्री विमान में बम विस्फोट होने से हवाई जहाज पर सवार चालक दल के सात सदस्यों सहित सभी 105 यात्री मारे गए थे. संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी और दुबई के बीच इस हवाई जहाज में रखे सामान में विस्फोट हो गया था. इस जहाज में जो यात्री मारे गए उनमें ज्यादातर वे लोग थे जो पाकिस्तान में अपने घरों में ईद की छुट्टियों के बाद काम पर वापस जा रहे थे. ■■

- 1780-अमेरिकी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के मेजर जॉन आंद्रे अमेरिका में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार.
- 1803-भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच युद्ध.
- 1929-बाल विवाह विरोधी विधेयक पारित.
- 1939-सिगमंड फ्रायड का निधन.
- 1965-भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा.
- 1983-सेंट किट्स और नेविस संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने.
- 1993-दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों को सरकार बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार मिला.

पाठकों के पत्र

गरीब बनें राजनीति का केंद्र

आर्थिक नीतियों का पैमाना राजनीति पर ज्यादा आधारित होता है. हम चाहे कितने ही विकास के दावे कर लें, फिर भी विकास के तमाम दावों की सरकार की पोल खुल ही जाती है और इसीलिए आज गरीब वर्ग के मजदूर और किसान नारकीय जिंदगी जी रहे हैं. जब तक जमीन से जुड़ा हुआ हमारा मजदूर व किसान राजनीति का केंद्र नहीं बनेगा तब तक हम विकास को विकास नहीं कह पाएंगे.

■ डी.जी. घुले, नागपुर

नक्शों का हो इस्तेमाल

अखबारों में जब अंतर्राष्ट्रीय खबरें छपती हैं तो उस खबर के आजू-बाजू में अगर विश्व का नक्शा लगाकर उसमें खबर से संबंधित देश को चिह्नित करके दिखाया जाए तो पाठकों को उस खबर को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकती है.

■ एस.एस. दाभ, नागपुर

आप भी अपने पत्र हमें lsedit.ngp@lokmat.com पर मेल कर सकते हैं या डाक पते पर भेज सकते हैं.

विश्वास का फल

अमेरिका की बात है. एक युवक को व्यापार में बहुत नुकसान उठाना पड़ा. उस पर बहुत कर्ज चढ़ गया. एक दिन वह चिंतित बैठा था. तभी एक बुजुर्ग वहां पहुंचे और चिंता का कारण पूछा. उसकी कहानी सुनकर बोले -''मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है. मैं तुम्हें नहीं जानता, पर तुम मुझे सच्चे लग रहे हो. इसलिए मैं तुम्हें दस लाख डॉलर का कर्ज देने को तैयार हूं.'' फिर जेब से चेकबुक निकाल उन्होंने रकम दर्ज की और देते हुए बोले, ''नौजवान, आज से ठीक एक साल बाद हम इसी जगह मिलेंगे. तब तुम मेरा कर्ज चुका देना.''

विविध

युवक चकित था. जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे. अचानक उसके मन में ख्याल आया, एक अपरिचित व्यक्ति ने मुझपर भरोसा किया, पर मैं खुद पर भरोसा नहीं कर रहा हूं. उसने निश्चय कर लिया कि चेक का इस्तेमाल न कर घनघोर मेहनत करेगा. उसकी कोशिशें रंग लाने लगीं. साल भर बाद तो वो पहले से भी अच्छी स्थिति में था. निर्धारित दिन ठीक समय वह बगीचे में पहुंच गया. वह चेक लेकर राह देख रहा था कि वे दूर से आते दिखे. जब वे पास पहुंचे तो युवक ने श्रद्धा से उनका अभिवादन किया. उनकी ओर चेक बढ़ाकर कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही था कि एक नर्स भागते हुए आई और झपट्टा मारकर वृद्ध को पकड़ लिया. युवक हैरान रह गया. नर्स बोली, ''यह पागल बार-बार पागलखाने से भाग जाता है और लोगों को जॉन डी. रॉकफेलर के रूप में चेक बांटता फिरता है.''

अब वह युवक पहले से भी ज्यादा हैरान था. ■■